



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1175]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2010/ज्येष्ठ 21, 1932

No. 1175]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2010/JYAISTHA 21, 1932

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2010

का.आ. 1399(अ).—आदर्श ग्रामोद्योग समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया है) द्वारा राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आयोग कहा गया है) को, विपणन विकास सहायता के लिए किए गए अधिक भुगतान के लिए वर्ष 2006-2007 के लिए सत्ताइस लाख तीस हजार नौ सौ नवासी रुपये और सड़सठ पैसे मात्र और वर्ष 2007-2008 के लिए छब्बीस लाख अड़तीस हजार दो सौ पचहत्तर रुपये मात्र सहित कुल तिरपन लाख उनहत्तर हजार दो सौ चौसठ रुपये और सड़सठ पैसे मात्र की राशि का भुगतान किया जाना है;

और आयोग ने उक्त समिति द्वारा तिरपन लाख उनहत्तर हजार दो सौ चौसठ रुपये और सड़सठ पैसे मात्र की उक्त राशि वापस लौटाने के लिए एक पत्र जारी किया;

और उक्त समिति ने उक्त आयोग को तिरपन लाख उनहत्तर हजार दो सौ चौसठ रुपये और सड़सठ पैसे मात्र की राशि जिसके अंतर्गत ब्याज/दंड ब्याज भी है, के भुगतान करने की अपनी भुगतान देयता का विरोध करते हुए आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन किया और उक्त समिति से तिरपन लाख उनहत्तर हजार दो सौ चौसठ रुपये और सड़सठ पैसे मात्र की उक्त राशि की वसूली करने से आयोग को रोकने के लिए एक आदेश जारी करने की प्रार्थना करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की;

और माननीय उच्च न्यायालय ने निदेश दिया कि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उप-धारा (2) के निबंधनों के अनुसार केंद्रीय सरकार, उक्त समिति द्वारा उठाए गए विवाद को, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19ख में दी गई विवाद के अर्थ में एक विवाद के रूप में मानेगी तथा आयोग और उक्त समिति के मध्य विवाद के समाधान के लिए एक अधिकरण का गठन करेगी।

अतः अब, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नियम, 2006 के नियम 30 के उप-नियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61), की धारा 19 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, उक्त समिति द्वारा आयोग की देयताओं के भुगतान के प्रश्न के विनिश्चय करने के लिए एक व्यक्ति से गठित अधिकरण, अर्थात् श्री एस.के. गोयल, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011, का गठन करती है।

यह अधिकरण, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 मास के अर्धिन केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
उक्त अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा. सं. सी-18019/14/2009-केवीआई-II]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2010

S.O. 1399(E).—Whereas, a sum of rupees fifty three lakh sixty nine thousand two hundred sixty four and paise sixty seven including rupees twenty seven lakh thirty thousand nine hundred eighty nine and paise sixty seven for 2006-2007 and rupees twenty six lakh thirty eight thousand two hundred and seventy five for 2007-08 on account of excess payment made towards Market Development Assistant is payable by the Adarsh Gramodyog Samiti (hereinafter referred to as the said Society), to the State Director, Khadi and Village Industries Commission (hereinafter referred to as the said Commission);

And, whereas, the Commission issued a letter to the said Society to refund the said amount of rupees fifty three lakh sixty nine thousand two hundred sixty four and paise sixty seven only;

And whereas, the said Society has disputed its liability to pay the said sum of rupees fifty three lakh sixty nine thousand two hundred sixty four and paise sixty seven only including interest/penal interest to the said Commission, represented to the Chief Executive Officer of the Commission and filed a writ petition before Delhi High Court praying for issuing an order restraining the Commission from effecting recovery of the said sum of rupees fifty three lakh sixty nine thousand two hundred sixty four and paise sixty seven only from the said society;

And whereas, the Hon'ble High Court directed that, in terms of sub-section (2) of Section 19 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 the Central Government shall treat the dispute raised by the said Society as a dispute within the meaning of Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 and constitute a Tribunal to settle the dispute between the Commission and the said Society.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission, Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of one person, namely Shri S.K. Goyal, Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhavan, New Delhi-110011 to decide the question on payment of dues by the said Society to the said Commission.

The said Tribunal shall submit its report to the Central Government within three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The headquarters of the said Tribunal shall be at New Delhi.

[F.No. C-18019/14/2009-KVI-II]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.